NREGA WEEK BULLETIN

Sunday, July 9, 2006, Bhopal

PACS NREGA WEEK

JULY 3 TO JULY 9, 2006

YUVA, Betul

8th July, Devpur Kotmi village, Chicholi block, Betul district

YUVA, Betul team, is celebrating PACS NREGS week with great enthusiasm & dedication. In this sequence, on 8th July, 2006, they organized a large meeting in Devpur Kotmi village, situated about 50 km from the district headquarters. In this meeting, a total 120 men & women participated.

The YUVA team facilitated the meeting on various NREGS issues. Samavesh, as a Resource Organisation (RO), facilitated the interaction by exchanging information with the community on issues and pitfalls in implementing and accessing the NREGA scheme. Community members asked several questions on issues like daily wages under NREGS, employment opportunities, filling/filing application forms and so on, and also spoke about receiving only Rs. 20-25 per day as wages for a day's hard work for work done under the scheme.

Main points raised by villagers during campaign

Why are the panchayat secretary & Sarpanch giving less wages against hard work? Shri Laal listed out more than 60 per-

sons who had received only Rs. 20-25 per day against the minimum wage of Rs. 61.37, and as also mentioned by the Panchayat secretary in the job cards. The Secretary also delayed the distribution of job cards even after entry of work & was also refusing to put his signature on the cards. According to the villagers and from site inspection by our team members, the persons employed for labour had worked hard cutting and digging hard rocks up to 10 feet in depth and carrying the excavated dirt and debris up more than 20 feet distant.

Members are aslo not aware about monitoring & vigilance committees to ne set up just to avoid these kind of situations of exploitation and callousness.

What YUVA decided to do with community?

YUVA team members prepared a memorandum that demended that all information like actual wages received are recorded in the job card, as also work details and signatures of applicants. The memorandum was for submission to the Janpad Panchayt & District Collector respectively.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमन चाइल्ड एण्ड यूथ डेव्हलपमेंट

म०प्र० ग्रामीण रोजगार योजना में संस्था की भूमिका

म०प्र० में रोजगार गारंटी योजना शुरू होने के पश्चात डिण्डौरी मे सस्था ने ५० गांवों का माईक्रो प्लान जो हमने स्वयं समर्थन प्रकल्प को चलाते हुए बनाये थे को जिला कलेक्टर के पास जमा किया। उसी आधार पर उन गांवों के कामों की स्वीकृति मिली।

जब काम की शुरूआत करने में सारे सरपंच कतरा रहे थे तब प्रशासन से हम मिले कि रोजगार योजन्तगंत कार्य क्यों नहीं शुरू नहीं हो पा रहे है।

इसी बीच संस्था के चार कार्यकर्ता राजस्थान के डुंगरपुर १० दिवसीय पद यात्रा में शामिल हुए तथा वहाँ आयोजित कार्यशाला में भी भाग लिये। वहाँ की सीख लेकर हमने डिण्डौरी जिले में भी दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें स्वयं समर्थन कार्यक्रम के कार्यकर्ता तथा ग्रामदूतो ने भागीदारी की। इसी कार्यक्रम में जिला पंचायत के मास्टर ट्रेनर ने भाग लेकर प्रतिभागियों के सवालों का उत्तर दिया। कार्यशाला के दूसरे दिन दूसरे सत्र में हम प्रतिभागियों को रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत चल रहे काम को दिखाने सक्का गांव गये। जहाँ हम मजदूरों से मिले व उनकी बातें सुनी। वहाँ पर पानी की सुविधा के अलावा कुछ नहीं था। छांव की व्यवस्था नहीं थी, दवाई की व्यवस्था नहीं थी, कार्यस्थल पर ६ बच्चे ६ साल तक के थे जिनके लिए झूलाघर की व्यवस्था नहीं थी। कार्यस्थल पर मस्टर रोल भी नहीं था। मस्टर रोल भरा ही नहीं जा रहा था। काम नाम कर नहीं दिया जा रहा था। कहने का तात्पर्य कि सारे मानदण्डो को ताक पर रख कर कार्य किये जा रहे थे।

हमने प्रशासन से जानना चाहा कि जिले में कार्य क्यो नही शुरू करवाये जा रहे हैं। इसी समय डबरा-डबरी बनाने का कार्यक्रम आया। इस कार्य को लेकर न तो प्रशासन में स्पष्ट समझ थी और न गांव स्तर पर। पंचायते इस कार्य को करने में झिझक रहीं थी। जिला कलेक्टर व जिला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ बैठके की गई। उसके पश्चौत जनपद पंचायत

के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के साथ भी बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में हमारे संकुल समन्वयको ने भाग लिया। बात नहीं बनी तो जिला पंचायत के अधिकारियों की उपस्थिति में बैठकों का आयोजन किया गया।

कार्य शुरू होने में लेट लतीफी देख हमने प्रशासन को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। यह पेशकश इस सोच के साथ दी गई कि जल संरक्षण की संरचनाओं का निर्माण वर्षा पूर्व सुनिश्चित हो साथ ही हम ग्रामीणों को भी तैयार करते जायेगे।

अंततः प्रशासन ने हमारे कार्यक्षेत्र में म० प्र० ग्रामीण रोजगार गारंटी का कार्य संस्था के जिम्मे दे दिया। हम लोगो के साथ बैठे तथा समझाइस दी कि तालाब व डबरा डबरी बनवाने से भूमि की नमी बनी रहगी, खेतो में एक अतिरिक्त फसल ली जा सकेगी। मछली पालन किया जा सकता है। वर्षा के पानी को रो. कने का एक ही तरीका है कि जगह जगह इस प्रकार की संरचनाओं का विकास किया जाये।

अंततः लोगों के द्वारा प्रस्ताव आने लगे। संस्था ने प्रस्ताव लेने के लिए प्रपत्र भी अपनी ओर से छपवाये हैं। सारे प्रस्तावों को इकट्ठा कर हमने जनपद पंचायत में जमा की। जिसकी एक प्रति जिला पंयायत में भी जमा किया गया। इस प्रकार हमने डबरा डबरी व तालाबो के ले आउट कार्यकताओं के माध्यम से डलवाये। और खुदने लगे डबरा-डबरा तथा तालाब। इन तालाबों को देखकर सुखद आश्चर्य भी होता है।

बीच-बीच में कार्य प्रगति का प्रतिवेदन भी सरकार को भेजते रहे। संवेदनशील जिला कलक्टर भी कई बार लोगों द्वारा किये जा रहे कार्यो को देखने आये।

३/०७/०६ को संस्था ने रोजगार गारंटी व आजीविका विषय पर सरपंच सम्मेलन/कार्यशाला का आयोजन किया। जिसमें १११ प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री डा० ई रमेश तथा विशिष्ट अतिथि जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एन. सेलवेन्द्रन रहे। यह कार्यशाला श्री राजेश मालवीय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम में हमारी रूचि का मात्र एक कारण रहा या यों कहें कि हमने संस्था की भूमिका सिर्फ जन जागरूगता तक न सीमित कर कार्य करवाने की तरफ भी गये ।

हमे जाना पड़ा। क्यों कि हमें डर हमेंर था कि कहीं इस योजना की दशा भी और योजना की तरह न हो जाये जिसमें नाम मात्र का काम होता था। हमने जिम्मेदारी महसूस की कि एक तरफ लोगों को भी तैयार करना है जागरूक करना है दूसरी तरफ कामों को भी शुरू करवाना था। जब गाड़ी स्टार्ट ने हों तो धक्का देकर शुरू करना पड़ता है, वही कार्य हमने किया। इसके लिए हमने हर १० दिन में प्रशासन को पत्र लिखा जिसके कारण कार्य को गति देने में सुविधा हुई । अभी तक हमारे कार्य क्षेत्र में ६६ डबरा-डबरी, १६ तालाब तथा ११२ कुओं का निर्माण हो चुका है। ६२ आंतरिक मिट्टी-मुरूम मार्गों का निर्माण भी कार्यक्षेत्र में हुआ है।

सारः-

लोग समझ गये हैं कि यदि विधिवत प्रस्ताव दिये जाये तो कार्य निश्चित ही होते हैं।

लल्लन प्रसाद गोंड
छप्ब्लक डिण्डोरी

CDC & SMS Balaghat

दिनॉक ८/७/२००६ को एन.आर.ई.जी.ए. जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों ने ३ गॉवों के लगभग ५०० से अधिक लोगों तक पंहुच बनायी, सी.डी.सी. संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम बरवाही, करवाही और हीरापुर में निम्नगतिविधियॉं आयोजित की गयीं।

- जागरूकता रैली
- सूचना स्टाल
- नुक्कड नाटक
- नुक्कड सभा
- फिल्म प्रदर्शन

ग्राम बरवाही में ढोल और बाजों के साथ समुदाय ने रैली में भाग लिया इससे पूर्व चलित सूचना स्टॉल का प्रदर्शन ग्राम में किया गया। रैली में ३०० महिला पुरूषों ने भाग लियाऔर एन.आर.ई.जी.ए. पर सूचना स्टॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त की।

८ से १३ वर्ष के ११ बच्चों द्वारा ग्राम बरवाही, हीरापुर में एन.आर.ई.जी.ए. पर बनाये गये नुक्कड नाटक का प्रदर्शन किया गया। इस नाटक का लेखन आनंद भारद्वाज और निर्देशन आनंद, छाया और ममता ने किया है। इस पूरे अभियान के लिए प्रचार सामग्री की व्यवस्था और सूचना स्टॉलें का प्रबंधन दारा सिंह द्वारा किया जा रहा है।

अभियान से काफी बातें निकल कर सामने आ रही है कई प्रश्न खडे हो रहे हैं, साथ ही प्रभाव भी पड रहा है, ग्राम लोटमारा के सरपंच ने अभियान की जानकारी मिलते ही मजदूरी का भुगतान किया और संस्था द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया, जबकि पहले लगभग १५ दिन बीत जाने के बावजूद मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था।

SSRO Visit

पेक्स के लिए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की एस.एस.आर.ओ. संस्था ताल के प्रतिनिधि श्री सौमित्र देव बर्मन इस समय बालाघाट जिले में हैं आज सी.डी.सी. और एस.एम.एस. के कार्यक्षेत्र में आयोजित जागरूकता गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। ग्राम हीरापुर में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए आपने कहा कि एन.आर.ई.जी.ए. को एक अधिकार के रूप में देखना चाहिए और अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए।

समपुड़ा एकीकृत ग्रामीण विकास संस्था (सिरडी)

ग्राम सावगढ़ (कलस्टर) में आयोजित म.प्र. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम २००५ के कम्पेनिंग की रिपोर्ट

१. सावलमेंढ़ा कलस्टर साप्ताहिक हाट के दिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम २००५ का प्रचार-प्रसार कम्पेनिंग सिर संस्था द्वारा लाऊट स्पीकर द्वारा अधिनियम की पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रावधान, प्रक्रिया व अन्य लिखित सामग्री को लोगों को समझाकर पढकर बताई गई।

२. इस हेतु संस्था ने म.प्र. रोजगार गारंटी की मुख्य बातों को लेकर एक पेम्पलेट प्रकाशित किया है जो लोगो को वितरित किये गये।

३. पेक्स द्वारा प्रकाशित पोस्टर भी लोगो को पढकर सुनाये गये व पंचायत स्तर पर चिपकाये गये।

४. लोग ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में कम ही जानते है। लोग जाब कार्ड १०० दिन का रोजगार के बारे में जानते है। अधिकांश लोगो को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जानकारी पंचायत और सिरडी संस्था से प्राप्त हुई।

सभी लोगों के जाब कार्ड पंचायत द्वारा बनाकर दिये गये इसके आवेदन की प्रक्रिया बहुत कम जगह अपनायी गई अधिकांश जाब कार्डो पर फोटो नही लगे है। लोगों ने काम की मांग नही की बल्कि सरपंच सचिव ने लोगो से आवेदन लेकर काम शुरू किया सभी लोगों को ५ कि.मी. के दायरे में काम मिला कई कई जगह मजदूरी का भुगतान एक महिना बाद किया गया इसमें टास्क फर्म के आधार पर रोजगार के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया गया लोगों को ६ दिन काम फिर एक दिन का अवकाश फिर ६ दिन काम इस तरह का रोजगार मिला शिकायत निवारण के लिये कही कोई प्रावधान नही था।

लोग मस्टर रोल के बारे में कम ही जानते है। कही पर भी प्राथमिक उपचार बाक्स की व्यवस्था नही थी। बच्चों की देखभाल के लिये महिला की नियुक्ति नही की गई बच्चे वाली महिलायें काम पर अपने बच्चे को लेकर नही आई पीने के पानी की व्यवस्था मजदुर लोग स्वयं करते है। जहां सडक आदि का काम चला वहां पेडे आदि की छाया थी। रोजगार गारंटी योजना के लागू होने के बाद पलायन में आंशिक कमी आई है। विकलांग लोगों को रोजगार नही दिया था।

५. इस योजना में काम पाने के लिये लोगों को आवेदन करना पडता है तथा योजना की प्रक्रिया में पढ़े लिखे मजदूरों की अहम भूमिका है। लेकिन अधिकांश ग्रामीण मजदूर कम पढे लिखे या निरक्षिर है अतः वे लिखित मांग नही कर सकते।

ग्राम पंचायत बानूर (कलस्टर) में आयोजित म.प्र. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की आयोजिन की रिपोर्ट

ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुल ३३२, जाब कार्ड बने है। इसमें से ११० आवेदक काम के लिये मिले। लगभग ११० लोगों को रोजगार मिला काम के आधार पर लोगो को ६१ रू. ३७ पैसे मजदूरी दी गई। इसमें सड़क का काम किया गया।

पंचायत ने अपनी ओर से काम चालू किया लोगों ने रोजगार की मांग नही की। पंचायत सचिव ने बताया कि म.प्र. रोजगार गारंटी योजना की खाता ही अलग है हमने मजदूरी का भुगतान ६१.३७ रू. प्रतिदिन के हिसाब दी है लेकिन इसका मूल्यांकन अभी नही हुआ है।

दिनांक
०६.०७.२००६

रैली में शामिल	**महिला**	**पुरूष**	**बच्चे**
	४१	१०	३०

जनप्रतिक्रिया

१. रोजगार गारंटी में रोजगार की मांग के बारे में लोग नही जानते है।

२. सभी के जाब कार्ड पर फोटो नही लगे।

३. जाब कार्ड पर काम की इन्ट्री नही की गई है।

४. ३५ परिवार को रोजगार मिला।

दिनांक ०३, ०४, व ०५ जुलाई २००६ को आयोजित कार्यक्रम में शामिल लोगों व गांवो की जानकारी व जनप्रतिक्रिया

दिनांक
०३.०७.२००६

गाँव/पंचायत
सावलमेढा (साप्ताहिक बाजार)

रैली में शामिल	महिला	पुरूष	बच्चे
	७३	१०	०५

जन प्रतिक्रिया

१. लोगो ने जानकारी ध्यान से सुनी

२. साप्ताहिक बाजार में धायवानी, पाटाखेड़ा, कोथलकुंड, धाबा, नत्थूढाना, गदराझिरी आदि ८-१० गांवों के लोग आये थे।

३. समूहों की महिलाओ ने रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया।

दिनांक
०४.०७.२००६

गाँव/पंचायत
खोमई (साप्ताहिक बाजार)

रैली में शामिल	महिला	पुरूष	बच्चे
	४८	१२	१६

जन प्रतिक्रिया

१. लोगों ने जानकारी ध्यान से सुनी

२. साप्ताहिक बाजार में खोमुई, सुपाला, पाटाखेड़ा, पिपलनाकला, पिपलनाखुर्द, साकली, खटगडा, आदि ०७ गावों के लोग आये थे।

३. समूहों की महिलाओं ने रैली में बढ चढकर भाग लिया।

दिनांक
०५.०७.२००६

गाँव/पंचायत
नत्थूढाना (अम्बाडा)

रैली में शामिल	महिला	पुरूष	बच्चे
	६६	२०	२०

जन प्रतिक्रिया

१. सरपंच ने भी लोगों को टास्क टर्म के बारे में जानकारी दी।

२. गांव में सभी के जाब कार्ड बने है ३६४ जाब कार्ड

३ जिन लोगों ने काम किया है उनको भुगतान किया गया है।

४. १८ वर्ष कम के बच्चे भी काम करने गये थे।

दिनांक
०४.०७.०६

गाँव/पंचायत

षोथी

रैली में शामिल	महिला	पुरूष	बच्चे
	२७	१२	१५

जनप्रतिक्रिया

१. एस.एच.जी की महिलाओं ने रैली में बढ़कर भाग लिया

२. ८७ परिवारों ने काम किया

३. ३३२ जाब कार्ड है

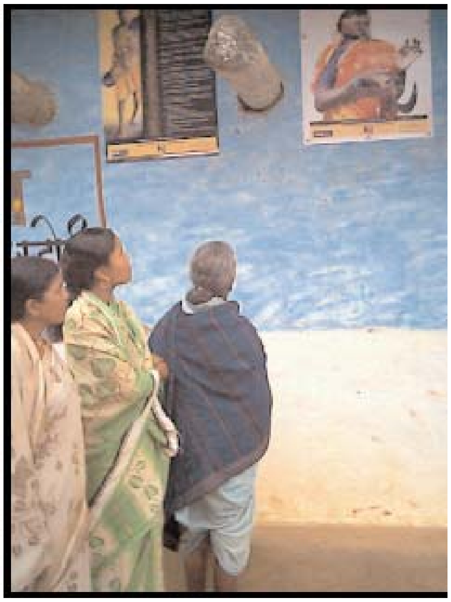

Earlier Initiatives

डुंगरपुर, राजस्थान पदयात्रा सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान

दिनांक १५/०४/०६से २६/०४/०६ तक सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान चलाया गया जिसे मजदूर किसान शक्ति संगठन राजसमंद, वागड़ मजदूर संघ डुंगरपुर व देश के सभी संगठनों के संयुक्त प्रयास से चलाया गया। चूंकि राजस्थान में चले सामूहिक काम के अधिकार अभियान व आंदोलन को मजबूत करते हुए ही यह ऐतिहासिक कानून आ पाया। कहा जाय कि नेताओं को जनता की राष्टव्यापी मांग व आंदोलन के चलते इस कानून को लाना पड़ा।

इस अभियान में भाग लेने के लिए २१ प्रदेशों के १२० संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही इस अभियान में बंगलादेश के १०, अमेरिका के १ तथा जर्मनी के दो प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इस अभियान के अन्तर्राष्टीय स्तर का अभियान बनाया।

इस अभियान में करीब ६०० लोगों की सक्रिय भागीदारी रही। अभियान की तैयारी में १५, १६ अप्रेल को प्रशिक्षण दिया गया तथा पद यात्रा दलों का गठन किया गया। कुल ३१ टीमें बनाई गई। दिनांक १७/४/०६ से अभियान की शुरूआत की गई। सबसे पहले डुंगरपुर शहर में रैली निकाल कर पद यात्रा का शुभारंभ किया जिसे जिला पंचायत के अध्यक्ष ने झंडी दे कर रवानो किया। टीमों को दो बजे से वाहनों द्वारा उस स्थान पर छोड़ा गया जहाँ से उन्हें यात्रा शुरू करनी थी। ३१ टीमें जिले के हर पंचायत के हर गांव तक पहुँची।

टीमें हर उस काम की जगह पहुँचीं जहाँ काम चल रहा था। हर टीम को साथ में मार्च ०६ तक किये गये कार्यो के सभी मस्टर रोल की छाया प्रति, पम्पलेट, पर्चे, बैनर, झंडे तथा बेचने के लिए साहित्य दिया गया था। हर टीम के साथ कठपुतली, ढोलक, व अन्य वाद्य यंत्र थे। हर टीम का समन्वयक एक स्थानीय व्यक्ति को बनाया गया था तथा हर टीम में डुंगरपुर का एक व्यक्ति जरूर था। हर व्यक्ति को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई थीं।

भाषण देना, दीवाल लेखन, शोध करना, सामाजिक अंकेक्षण, दान पेटी को संभालना, गीत-वादन आदि कार्य बांटकर दिये गये थे।

हमारे दिन का शुभारंभ सुबह ६ बजे से हो जाता था। स्थानीय लोग अपने घर में चाय पिलाने के लिए ले जाते थे। हम लोग ७.३० तक अगले पड़ाव के लिए निकल जाते थे। हम लोग सीधे अगली पंचायत के उस गांव पहुंचते थे जहाँ रोजगार गारंटी का काम चल रहा होता था। काम कर रहे लोगों को हम एक जगह बुलाकर अपने आने का कारण व परिचय देते थे।

फिर लोगों को इस योजना के बारे मे विस्तार से बताया जाता था। लोगों के अधिकार व कर्तव्यों की भी चर्चा होती थी। साथ ही सभी साथी अपने अपने काम को करते थे। शोध करने वाले शोध पत्र भरते थे। इसी स्थान पर लोग जो भी खाने के लिए लाये रहते थे उसमें से मांग कर खाते थे या दोपहर में एक एक व्यक्ति प्रत्येक घर में जाकर खाते थे। इस खाने के समय में भी कुछ विशेष फार्मेट भरे जाते थे खासकर छोटे बच्चे वाली माताओ से । इस प्रकार से इस पंचायत के हम हर काम को देखते थे। १ से ३ बजे के बीच में हम पंचायत कार्यालय जाते थे जहाँ सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया चलाई जाती थी। रोजगार गारंटी से संबंधित हर फाईल व कागज को देखा जाता था ।

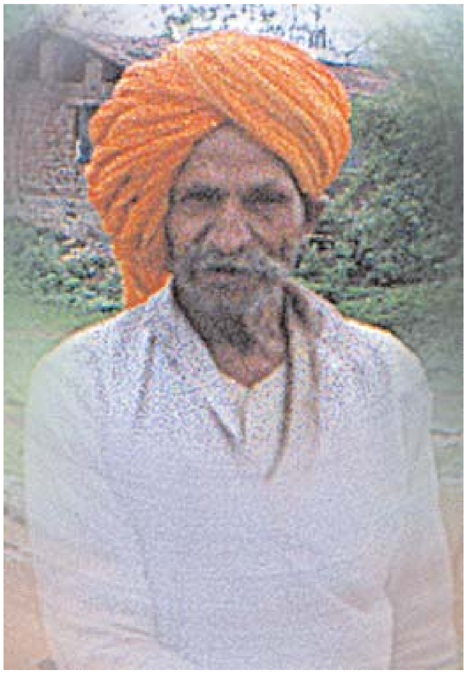

सचिव व सरपंच से सवाल भी किये जाते थे और यह सब काम जनता के सामने किया जाता था। यहाँ जनता को भाषण, गायन आदि के माध्यम से कानून की जानकारी दी जाती थी। यह कार्य करके गांव के बीच से गाते बजाते अपने रात्रि पड़ाव की तरफ चल पड़ते थे। रास्ते में काम लगा हो तो अपनी प्रक्रिया में लेते थे। रात का भोजन भी हम अलग अलग लोगों के यहाँ ही खाते थे खासकर गरीब लोगों के यहाँ। रात आठ बजे तक खाना खाकर फिर गांव में बैठक ली जाती थी, भाषण, नारे गीत तथा नाटक के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती थी।

गांव के लोग भी गाना सुनाते। इस प्रकार रात बारह बजे तक हम सो पाते थे। जिसकी जिम्मेदारी समाचार बनाने की थी वह दिन में १२ बजे तक समाचार डुंगरपुर भिजवाने की व्यवस्था करता था। रोज का समाचार अखबार में भी छपता था। दिनांक २५/०४/०६ को रात ८बजे हमारी टीम वापस डुंगरपुर पहुंची। हमारी ०२ नम्बर की टीम थी जिसने कुल रू० ३७८९ का चंदा जुटाया था।

इस पद यात्रा से निकलकर आये मुद्दे इस प्रकार हैंः

१. अभी लोग काम की मांग नहीं कर रहे हैं आशय ये कि उन्हें यह नहीं मालूम कि काम के मांग के लिए भी फार्म भरना है।

२. अभी तक कोई भी भत्ता की प्रक्रिया में नहीं गया है।

३. मस्टर रोल भरने में गड़बड़ी पाई गई। कार्यस्थल पर मस्टर रोल में उनकी भी हाजिरी लगी पाई गई जो कार्य स्थल पर मौजूद नहीं थे।

४. हर कार्य स्थल पर कार्य का माप अलग अलग दिया गया था।

५. मेठ को माप का ज्ञान नहीं था। न ही उनका प्रशिक्षण करवाया गया था।

६. कार्यस्थल पर बोर्ड नहीं था। यदि था तों उपयुक्त जानकारी नहीं लिखी गई थी।

७. कार्य कर रहे लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि इस कार्य के लिए कितने पैसे आये है।

८. स्थल पर खड़े रहने वालों की हाजिरी लगाई गई थी।

९. स्थलों का चुनाव ज्यादातर अनुपयुक्त था। सिर्फ काम देने के लिए काम चल रहा था। उससे संसाधन निर्मित होगा, उसपर किसी का ध्यान नहीं था।

१०. हमारी ९ पंचायतों में एक पंचायत झलाप की कार्यालय की दीवार पर कुछ लिखा ही नहीं गया था जबकि योजना की सम्पूर्ण जानकारी दीवार पर लिखना जरूरी है। उस पंचायत में आज तक कुछ लिखा ही नहीं गया।

११. सीमलवाड़ा पंचायत जो कि विकासखण्ड भी है में एक पानी भरने लायक स्थान के बीच में ही एक बांध बनवाया जा रहा था।

१२. सूखाराहत के कार्यो जैसी लोगों की आदत पड़ी हुई है जिसमें काम न करने कि बावजूद भी लोगों ने लाभ लिया है।

१३. किसी भी स्थान पर क्रेश/बालवाड़ी की व्यवस्था नहीं थी।

१४. किसी भी स्थान पर छाया की व्यवस्था नहीं थी।

१५. दवा-गोली की व्यवस्था कहीं नहीं थी।

१६. जॉब कार्ड रजिस्टर में एक ही व्यक्ति के अंगुठे कई जगह पाये गये।

१७. जॉब कार्ड रजिस्टर में लोगों के हस्ताक्षर नहीं थे।

१८. जॉब कार्ड में यह अंकित नहीं है कि कितने दिनों के लिए कार्य मागा गया है।

अनुत्तरित प्रश्नः

१.गर्भवती महिला को जिसके गर्भ काल के छः माह से उपर चल रहे हैं।

२.बुजुर्ग जो काम करने की स्थिति में नहीं है।

उपरोक्त जब काम की मांग करते हैं तब इनके काम का स्वरूप क्या होगा।

विषेशः

इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। प्रशासन ने अभियान को सकारात्मक रूप में लिया। प्रशासन ने मार्च २००६ तक के जिले भर के मस्टर रोल की छाया प्रति उपलब्ध करवाई थी।

जिले के हर विकास खण्ड के हर पंचायत को सूचना थी कि टीमें गांव में पहुँच रही हैं। जहाँ भी गड़बड़ी की सूचना दी गई तत्काल कार्यवाही की गई। समाचार पत्रों ने भी अभियान को मुख पत्र पर जगह दी। तीन टीमों के साथ दुर्व्यवहार की खबर पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख कर कार्यवाही की गई।

लल्लन प्रसाद गौड़

डिण्डौरी

PACS - SRIJAN film on NREGS

Nukkad Natak training for SRIJAN

The NREGA padyatra taken out by SRIJAN in Jatara block in April had a spin off. The CSO was requested by the Zila Panchayat CEO Mr BK Singh to develop a film around the NREGA. Supported by the State-based Communications organization Write Solutions, the preliminary groundwork for the film was chalked out.

In the first phase Shailendra Singh of Write Solutions, who has several years of experience in training development professionals and grassroots workers/artists as communicators, took up the task in the early June, 2006.

In the first deliberations with the CSO, Shailendra Singh tried to understand what they wanted and what could be done in the situation and the given budget. The consensus of these meetings was a film. Now who would be the main actors? SRIJAN opted for villagers as their main protagonists.

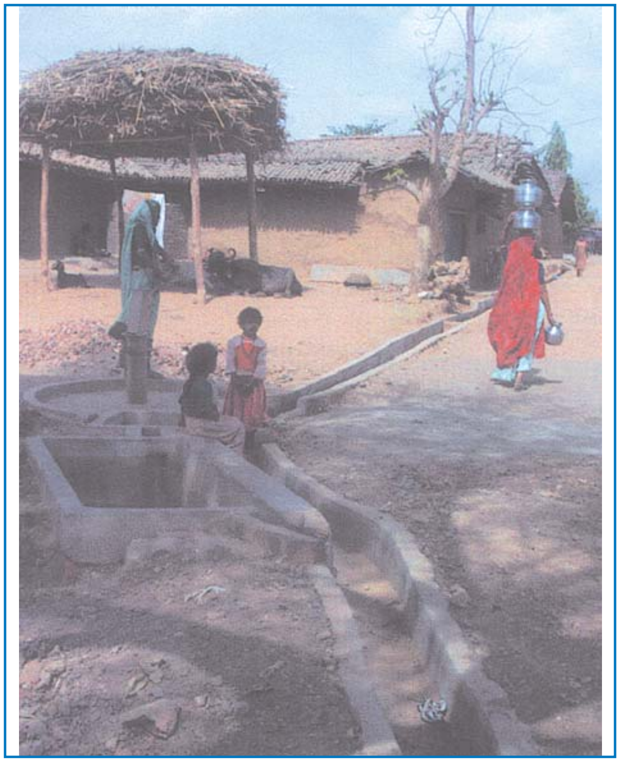

Zila Panchayat CEO Mr BK Singh's concern about the scheme was the basis for the film. How can a person who has not got the job card access the scheme. Armed with literature produced by PACS partners in Madhya Pradesh on the NREGA and RTI, Shailendra Singh began scripting the film.

In the second stage, SRIJAN selected villagers for the filming and with additional scouting for characters by Shailendra Singh the film team got down to business. Shailendra Singh explains, "The issue is an important one and we needed some mature people of some specific roles. People. who would have a screen presence and would be able to emulate gestures and postures."

Although Shailendra Singh made some interesting selections, after many hits and misses, they were finally able to put their team together. In the team was a paan shop owner Raghavendra, who had a some experience of Ram Leela's and for his part Shailendra Singh got him to grow a beard. With another villager Deendayal who was to play the main character Shailendra Singh, kept him engaged and deprived him of sleep to get him into the character of Dinu.

Explaining the significance of giving the actors the feel of their character Shailendra Singh says, "The actors need to feel, look and think like the character that they are portraying." He followed the same process for the hassled wife. One villager, Shankar played up to three roles in the film!

Over coming difficulties of working with rake amateur artistes who had never faced the camera, after six days of rigorous training they were ready to shoot a film that was as close as it could be to their lives.

Nukkad Natak training for Sambhav

A six-day residential nukkad natak training was held by Shailendra Singh for Bundelkhand CSO Sambhav in PACS project areas Rajnagar and Prithvipur. Nearly 20 to 22 people from the CSOs animator level attended each of these workshops .

Over six days, Shailendra Singh introduced participants to importance of theatre, why theatre is used, various modes

of communication, how to identifying issues, what is communication, parts of play, acting/scripting, the art of acting, the history of acting ,acting and art, song, music and drama, making story/script, making a story, the formula: Problems+ Action + Reaction + Solution = Story, acting and improvising, lifting participants inhibitions, games and songs, identifying the story.

He especially stressed on "Trying to touch people - touching people's hearts and emotions" with their storylines and theatre.

The nukkad natak workshop at Khajuraho was held between June 14 to 19, 2006, and the workshop at Prithvpur was held between June 21 to 26, 2006. At the conclusion of both workshops, field performance of the nutad nataks prepared at the workshops were held.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सप्ताह का भव्य समापन समारोह

९.७.०६

नमन सेवा समिति आठनेर द्वारा पैक्स कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड आठनेर के १६ गांवों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सप्ताह दिनांक ३.७.०६ से ९.७.०६ तक मनाया गया। इस दौरान हर गांव के नमन प्रेरक, संस्था प्रेरक, कार्यक्रम समन्वयक, अध्यक्ष नमन सेवा समिति एवं संगीत मंडली के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के महत्व एवं नियमों की जानकारी दी।

इस कार्यक्रम का समापन विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत के सभा कक्ष में किया गया। इस कार्यक्रम में वी.एन. त्रिपाठी समावेश भोपाल ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के महत्व एवं नियमों की जानकारी दी। श्री एस के मोदी सीईओ जनपद पंचायत आठनेर ने जाब कार्ड, टास्क रेट एवं कार्य की गुणवत्ता के बारे में समझाया । इस अवसर पर राजीव गांधी शिक्षा मिशन खंड समन्वयक भरत शर्मा, सहदेव डांगे, उपसरपंच टेमुरनी, श्री शिशिर कुमार चौधरी अध्यक्ष नमन सेवा समिति, कार्यक्रम समन्वयक अब्दुल सप्तार काजी, संस्था प्रेरक एवं स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

PACS NREGA WEEK

JULY 3 TO JULY 9, 2006

Compiled by Write Solutions, Bhopal, Communications Resource Organisation for PACS.

For more information about the PACS programme in MP & CG, please write to us at E4/185, Arera Colony, Bhopal-462003 (MP) or mail us at pacsindia@devalt.org. You can also call +91 755 4202234 .